IJAER/Jan-Feb 2022/Volume-11/Issue-1 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

भारतीय अर्थवस्था में रोजगार के स्तर

भारत भूषण
शोधार्थी
ओ पी जे एस विश्वविद्यालय चूरू राजस्थान

राजेंद्र सिंह
प्रोफेसर
ओ पी जे एस विश्वविद्यालय चूरू राजस्थान

सार

यह अध्ययन भारतीय अर्थवस्था में रोजगार के **स्तर** पर किया गया है भारत की रोजगार प्रक्रिया में निरंतर विकास हो रहा है जो हमारी भारतीय अर्थवयवस्था के लिए मत्वपूर्ण भी है और आवशयक भी है वर्तमान में आय के बढ़ते स्तर ने कई और सेवाओं की मांग पैदा कर दी है जैसे कि बाहर खाना, पर्यटन, खरीदारी, निजी अस्पताल, स्कूल आदि पिछले चार दशकों में रोजगार का पैटर्न बदल गया है।

मुख्य शब्द: रोजगार, अर्थवस्था.

प्रस्तावना

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में भारत के एक विशालकाय के रूप में उभरने की दृष्टि अपने विकास प्रदर्शन पर समकालीन चर्चा पर हावी होती दिख रही है, जिससे "अद्भुत भारत", "चमकता भारत" आदि जैसे वाक्यांशों का गढ़ा हुआ है। अर्थव्यवस्था की गतिशीलता को शैलीबद्ध तथ्यों के माध्यम से पेश किया गया है

जैसे कि भारत ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीपों के बराबर है और यह लगभग ढाई दशकों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था से आगे निकल जाएगा। 2002–07 की दसवीं योजना अवधि के दौरान देश के 8: से अधिक विकास परिदृश्य और ग्यारहवीं योजना में 9: प्रति वर्ष के अनुमानित विकास लक्ष्य ने इस परिप्रेक्ष्य को मजबूत किया है। यहां तक कि 2008–09 के दौरान 7.2: की वृद्धि का अग्रिम अनुमान – वैश्विक आर्थिक मंदी का वर्ष – पिछले दशक के औसत से बहुत कम लेकिन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (2009) द्वारा अनुमानित और चीन की तुलना में थोड़ा अधिक है। ,

एक असाधारण उपलब्धि के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विकसित देशों के लिए अर्थव्यवस्था में 2: गिरावट के बावजूद चीन के साथ–साथ यह विकास विश्व अर्थव्यवस्था को विकास के सकारात्मक चतुर्थांश में रखने वाला प्रमुख कारक है – युद्ध के बाद की अवधि में पहला वार्षिक संकुचन। ये निस्संदेह खुशी के मामले हैं और फिर भी वे असमानता और गरीबी पर विकास की इस गतिशीलता के प्रभाव के बारे में सवाल उठाने के लिए कारण प्रदान करते हैं। सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों के तहत सृजित नौकरियों की मात्रा और गुणवत्ता, प्राप्त वेतन और श्रमिकों के कवरेज के संदर्भ में रोजगार के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करके इन सवालों की जांच करना महत्वपूर्ण होगा।

रोजगार हमेशा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में माना गया है। भारत एक अत्यधिक आबादी वाला देश होने के कारण, रोजगार एक महत्वपूर्ण तत्व बन जाता है। रोजगार आर्थिक विकास और गरीबी में कमी के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। समावेशी और सतत विकास की प्राप्ति में रोजगार एक महत्वपूर्ण चर के रूप में कार्य करता है। समग्र विकास योजना में रोजगार का ध्यान 1970 और 1980 के दशक के उत्तरार्ध में उभरा जब यह महसूस किया गया कि बेरोजगारी बढ़ रही है। 1990 के दशक के बाद के सुधारों की शुरुआत के साथ, आम तौर पर इसका विश्लेषण किया गया है कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधारों से प्रेरित विकास रोजगार पैदा कर रहा है या नहीं। महान मंदी ने वैश्विक स्तर पर और साथ ही भारत में मंदी के कारण बेरोजगारी और रोजगार सृजन के बारे में चिंताओं को और बढ़ा दिया है। भारत का समावेशी विकास तब तक हासिल नहीं होगा जब तक कि कुल रोजगार में अनौपचारिक रोजगार का हिस्सा कम नहीं हो जाता। हालाँकि, पूरे कार्यक्षेत्र का 90 प्रतिशत से अधिक अनौपचारिक (बिना किसी सामाजिक बीमा के परिभाषित), और 85 प्रतिशत गैर–कृषि कार्यबल के अनौपचारिक होने के कारण, भारत इस संबंध में निम्न–मध्यम आय वाले देशों में एक अलग है। हालांकि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है, लेकिन दशकों से अनौपचारिकता की घटनाएं इस स्तर पर अटकी हुई हैं। इस आंकड़े की चिपचिपाहट चिंता का एक गंभीर क्षेत्र बनी हुई है, यह देखते हुए कि श्रम बल में शामिल होने की संख्या केवल अगले दशक में 2030 तक बढ़ती रहेगी (जहां से श्रम बल में वृद्धि कम हो जाएगी)। भारत ने 1980 के दशक की शुरुआत से एक जनसांख्यिकीय लाभांश का अनुभव किया है, जो 2040 तक समाप्त हो जाएगा। स्पष्ट रूप से एक नीतिगत अनिवार्यता यह है कि न केवल गैर–कृषि नौकरियों को कम से कम श्रम बल में वृद्धि के अनुरूप दर से बढ़ना चाहिए, बल्कि गुणवत्ता की गुणवत्ता भी होनी चाहिए। नौकरियों में भी सुधार करना होगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार

समावेशी विकास, ग्यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं (2007–17) का लक्ष्य, अधिक गैर–कृषि रोजगार पैदा किए बिना हासिल नहीं किया जाएगा। इस पत्र का तर्क है कि 2004–05 के बाद से रोजगार में संरचनात्मक बदलाव, ग्रामीण मजदूरी में उल्लेखनीय वृद्धि, प्रति व्यक्ति खपत व्यय में वृद्धि और इसलिए 2009 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) द्वारा प्रदर्शित गरीबों की पूर्ण संख्या में तेज गिरावट –10 और 2011–12 ने एक अंतर्निहित प्रक्रिया शुरू की है जिसने समावेशी विकास को बढ़ावा दिया है। 2004–05 के बाद, जब एक संशोधित (तेंदुलकर) गरीबी रेखा ने निरपेक्ष और सापेक्ष गरीबी का अनुमान बढ़ाया, तो गरीबों की पूर्ण संख्या 2004–05 में 407 मिलियन से गिरकर 2009–101 में 356 मिलियन और 2011 में 26.9 मिलियन हो गई (ए 138 मिलियन की कुल गिरावट)।2 चिंता की बात यह है कि पिछले दशक में उत्पादन की संरचना और रोजगार की संरचना के बीच एक अलग प्रवृत्ति है, खासकर जब सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि में काफी वृद्धि हुई है। यह पेपर पिछले दो दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार में इसे और अन्य प्रवृत्तियों को समझाने का प्रयास करता है

व्यावसायिक संरचना के आधार पर एक अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्रों (ए) प्राथमिक क्षेत्र (बी) माध्यमिक क्षेत्र (सी) तृतीयक क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्राथमिक क्षेत्ररू अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र

वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग कर रहा है। इसमें कृषि, वानिकी, मछली पकड़ने, खनन आदि शामिल हैं।

1. **प्राथमिक क्षेत्र** आमतौर पर कम विकसित देशों में सबसे महत्वपूर्ण होता है और आमतौर पर विकसित देशों में कम महत्वपूर्ण होता है।
2. **द्वितीयक क्षेत्र :** द्वितीयक क्षेत्र में वे आर्थिक क्षेत्र शामिल हैं जो एक तैयार उत्पाद का उत्पादन करते हैं। यह क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन को इनपुट के रूप में लेता है और तैयार माल का निर्माण करता है।
3. **तृतीयक क्षेत्र :** इसे सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। इसमें अर्थव्यवस्था का "नरम" हिस्सा शामिल है, दूसरे शब्दों में इसमें वे गतिविधियाँ शामिल हैं जहाँ लोग उत्पादकता, प्रदर्शन और क्षमता आदि में सुधार के लिए अपना ज्ञान और समय देते हैं।

इसमें बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, परिवहन होटल, बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति आदि जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं। इसलिए इस क्षेत्र की मूल विशेषता अंतिम उत्पादों के बजाय सेवाओं का उत्पादन है। वर्तमान में आय के बढ़ते स्तर ने कई और सेवाओं की मांग पैदा कर दी है जैसे कि बाहर खाना, पर्यटन, खरीदारी, निजी अस्पताल, स्कूल आदि पिछले चार दशकों में रोजगार का पैटर्न बदल गया है। प्राथमिक क्षेत्र में कार्यबल का प्रतिशत 74.3: (1972–73 में) से घटकर 48.9: (2011–12 में) हो गया है। द्वितीयक क्षेत्र में कार्यबल का प्रतिशत 10.9 (1972–73 में) से बढ़कर 24.3 (2011–12 में) हो गया है।

उद्देशय

1. भारत में अनौपचारिक औपचारिक रोजगार की संरचना पर अध्ययन करना।
2. भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार पर अध्ययन करना।

भारत में अनौपचारिक औपचारिक रोजगार की संरचना

बिना लिखित अनुबंध, सवैतनिक अवकाश, स्वास्थ्य लाभ या सामाजिक सुरक्षा वाले कर्मचारी के रूप में परिभाषित अनौपचारिक कार्यकर्ता। तालिका 3 2011–12 से 2017–18 की अवधि में कार्यबल की औपचारिकता का बोध कराती है। रोजगार हिस्सेदारी के मामले में असंगठित क्षेत्र में 83: कार्यबल और 17: संगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। अर्थव्यवस्था में 92.4: अनौपचारिक कर्मचारी (बिना किसी लिखित अनुबंध, सवैतनिक अवकाश और अन्य लाभों के) हैं। आउटसोर्सिंग के स्तर को इंगित करने वाले संगठित क्षेत्रों में 9.8: अनौपचारिक कर्मचारी भी हैं। ये संभवतरू संविदा कर्मचारी हैं। 2017–18 में असंगठित क्षेत्र के रोजगार की हिस्सेदारी में 3.6 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई है जबकि दूसरी ओर औपचारिक रोजगार की हिस्सेदारी में 0.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। औपचारिक रोजगार के हिस्से में वृद्धि हुई है। यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के सरकार के प्रयासों को भी इंगित करता है।

तालिका 1 कुल रोजगार का वितरण (%)

मज़दूर	2011–12			2017–18		
	असंगठित	संगठित	कुल	असंगठित	संगठित	कुल
अनौपचारिक	82.6	9.8	92.4	85.5	5.2	90.7
औपचारिक	0.4	7.2	7.6	1.3	7.9	9.3
कुल	83.0	17.0	100.0	86.8	13.2	100.0

स्रोत: रोजगार बेरोजगारी, 2011–12 और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, 2017–18 पर एनएसएस की 68वीं इकाई स्तर के आंकड़ों से गणना

भारतीय अर्थव्यवस्था रोजगार (विजन 2020)

आय और धन में असमानता में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन केवल लंबी अवधि के परिप्रेक्ष्य में ही संभव है। किसी अर्थव्यवस्था का रोजगार ढांचा सामान्य साधन है जो असमानता में किसी भी तरह से बदलाव का कारण बन सकता है, यानी असमानता में वृद्धि या कमी। लक्ष्य समूह की नीतियों और कार्यक्रमों जैसे अन्य आर्थिक साधनों का अल्पकालिक प्रभाव होता है, लेकिन रोजगार के माध्यम से पुनर्वितरण टिकाऊ होता है। चूंकि सरकारें प्रशासनिक और राजकोषीय बाधाओं के भीतर काम करती हैं, लक्ष्य समूह के कार्यक्रमों का आम तौर पर आय पुनर्वितरण पर मामूली प्रभाव पड़ता है। श्रम की आय लोगों के आय वर्गों और सामाजिक और जातीय समूहों में संसाधनों के प्रवाह को सक्षम बनाती है। विभिन्न स्थानों पर आय का प्रवाह उपलब्ध संपत्ति और रोजगार के अवसर पैदा करने के अन्य तरीकों दोनों से प्रभावित होता है। हालांकि, प्रवासी श्रमिकों के रोजगार से उत्पन्न आय, पूंजीगत संपत्ति के दिए गए क्षेत्रीय वितरण के लिए क्षेत्रों में संसाधनों के प्रवाह की सुविधा प्रदान करती है। इसलिए, लोगों के सभी वर्गों और क्षेत्रों में आय का रोजगार और इक्विटी, लंबी अवधि में एक–दूसरे से निकटता से संबंधित हैं।

आईटी और आईटीईएस के विकास में योगदान :– सेवा क्षेत्र ने भी आईटी और आईटी सक्षम सेवाओं के निरंतर विकास में मदद की है। देश का आईटी क्षेत्र युवा और शक्तिशाली क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ है।

इसने वैश्विक बाजार में ब्रांड पहचान अर्जित की है। इसके मुख्य घटक आईटी सेवाएं, इंजीनियरिंग उत्पाद हैं। आईटी और आईटी सक्षम सेवा क्षेत्र ने हमारी अर्थव्यवस्था में काफी मात्रा में राजस्व और रोजगार पैदा किया है। जीडीपी में आईटी और आईटीईएस क्षेत्र के राजस्व का अनुपात 1997–98 में 1.2: बढ़कर 2011–12 में 7.5: हो गया है। 2010–11 में 59 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 2011–12 में भारत का सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ 69 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। आईटी और आईटीईएस उद्योग में निर्यात का दबदबा बना हुआ है। यह कुल उद्योग राजस्व का लगभग 78.4: है।

2010–11 में आईटी और आईटीईएस और निर्यात क्षेत्र के घरेलू क्षेत्र की वृद्धि दर क्रमशः 20.6 प्रतिशत और 18.8ः थी। तो इस तरह अर्थव्यवस्था को उच्च विकास प्राप्त करने में मदद करना। इसके अलावा, देश में पिछले महीने कुल रोजगार में 3.3 मिलियन की कमी आई क्योंकि जनवरी में रोजगार दर दिसंबर में 37.2ः से घटकर 37.6ः हो गई, जबकि श्रम बल की भागीदारी दर दिसंबर 2021 में 40.9ः से गिरकर जनवरी 2022 में 39.9ः हो गई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के डेटा से पता चलता है कि भारत की श्रम शक्ति भागीदारी दर (एलएफपीआर) 2016 में पहले से ही कम 47ः से घटकर सिर्फ 40ः रह गई है। इससे न केवल यह पता चलता है कि भारत की आधी से अधिक आबादी काम कर रही है। –आयु वर्ग (15 वर्ष और अधिक) नौकरी बाजार से बाहर बैठने का फैसला कर रहा है, लेकिन यह भी कि लोगों का यह अनुपात बढ़ रहा है।

वर्तमान

भारतीय अर्थव्यवस्था 2024–25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण को प्राप्त करने की राह पर है। आर्थिक विकास रोजगार सृजन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। पिछले साल, बजट 2021–22 ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निवेश के प्रावधान में तेज वृद्धि प्रदान की थी। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करने के साथ, देश में आर्थिक सुधार को गुणक प्रभाव से लाभ मिल रहा है। 1 बजट 2022–23 ने विकास के लिए एक मजबूत गति प्रदान की है, पूंजीगत व्यय में 35.40 प्रतिशत की तेजी से वृद्धि की गई है, चालू वित्त वर्ष में 5.54 लाख करोड़ रुपये से 7.50 लाख करोड़ रुपये। यह परिव्यय, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.9 प्रतिशत है, न केवल आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा बल्कि साथ ही साथ देश में रोजगार की स्थिति में भी सुधार करेगा।

वर्तमान मैक्रो आर्थिक रुझान

पिछले दो वर्षों में कोविड–19 महामारी के कारण हुए भारी झटके और व्यवधानों के बावजूद, देश की अर्थव्यवस्था को धन देने और देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार द्वारा निरंतर धक्का देना शुरू हो गया है। कुछ आर्थिक संकेतक जैसे संगठित क्षेत्र में नौकरी नामांकन, पंजीकृत नई कंपनियों की संख्या में वृद्धि, स्टार्ट–अप की वृद्धि और देश में यूनिकॉर्न की संख्या में तेजी से वृद्धि, एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे नए क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि। डेटा एनालिटिक्स, आईटी/आईटीईएस के तहत ऑटोमेशन, आदि स्पष्ट रूप से देश में नौकरियों के सृजन में वृद्धि की ओर इशारा करते हैं।

ईपीएफओ सब्सक्रिप्शन में उछाल: ईपीएफओ डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि 2021 के दौरान जॉब मार्केट को औपचारिक रूप देने में महत्वपूर्ण तेजी आई है। नवंबर, 2021 में, मासिक शुद्ध अतिरिक्त म्ब्थ् सब्सक्रिप्शन 13.95 लाख नए सब्सक्राइबर्स के साथ चरम पर पहुंच गया, जो 2017 के बाद से किसी भी महीने में सबसे ज्यादा है। यह नवंबर, 2020 से ईपीएफ सदस्यता में 109.21 प्रतिशत की वृद्धि में तब्दील होता है। आर्थिक सर्वेक्षण में आगे कहा गया है कि 2021 के दौरान ईपीएफ सदस्यता में मासिक शुद्ध वृद्धि न केवल 2020 में इसी मासिक मूल्यों से अधिक रही है, बल्कि उन्होंने स्तरों को भी पार कर लिया है। पूर्व–महामारी वर्ष 2019 के दौरान इसी महीने की।

आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 2020 में देशव्यापी तालाबंदी के दौरान रोजगार चरम पर था। यह आगे बताता है कि दूसरी कोविड लहर के बाद मनरेगा के काम की मांग स्थिर हो गई है, यह दर्शाता है कि महामारी के कारण व्यवधान है। अपना दंश खो रहा है और अन्य क्षेत्रों में रोजगार के रास्ते खुल रहे हैं। दूसरी कोविड लहर के दौरान, मनरेगा रोजगार की मांग जून 2021 में अधिकतम 4.59 करोड़ लोगों के स्तर पर पहुंच गई। पीएलएफएस डेटा से मुख्य निष्कर्षरू 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) का अनुमान नियोजित की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। वर्ष 2017–18 से 2019–20 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर कुल जनसंख्या में व्यक्तियों में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई गई है, जबकि सामान्य आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक के लिए अनुमानित बेरोजगारी दर घटती प्रवृत्ति दिखा रही है। 2019–20 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुष और महिला व्यक्तियों के लिए श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) का अनुमान क्रमशः 76.8 प्रतिशत और 30.0 प्रतिशत है।

क्षेत्रवार रुझान

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने तिमाही रोजगार सर्वेक्षण (क्यूईएस) और ईपीएफओ पेरोल डेटा की हालिया सर्वेक्षण रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि देश में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र के नेतृत्व में सरकार प्रतिबद्ध है। संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में श्रमिकों और मजदूरों के कल्याण के लिए। 4 क्यूईएस रोजगार में वृद्धि दर्शाता है:

क्यूईएस जुलाई–सितंबर, 2021 के दौर में नौ चयनित क्षेत्रों में अनुमानित कुल रोजगार लगभग 3.10 करोड़ निकला, जो कि है फ्मै के पहले दौर (अप्रैल–जून, 2021) से अनुमानित रोजगार (3.08 करोड़) से 2 लाख अधिक। यहां यह उल्लेखनीय है कि छठी आर्थिक जनगणना (2013–14) में सामूहिक रूप से लिए गए इन नौ क्षेत्रों के लिए कुल रोजगार 2.37 करोड़ बताया गया था। एक्यूईईएस (अखिल भारतीय त्रैमासिक स्थापना–आधारित रोजगार सर्वेक्षण) को नौ चयनित क्षेत्रों के संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में रोजगार और प्रतिष्ठानों के संबंधित चर के बारे में लगातार (त्रैमासिक) अपडेट प्रदान करने के लिए लिया गया है, जो कि अधिकांश के लिए जिम्मेदार है। गैर–कृषि प्रतिष्ठानों में कुल रोजगार। नौ चयनित क्षेत्र विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रेस्तरां, आईटी / बीपीओ और वित्तीय सेवाएं हैं।

आईटीईएस/बीपीओ – एक विशाल उद्योग

आईटी/बीपीओ क्षेत्र सबसे बड़ा रोजगार सृजनकर्ता है और इसने परिवहन, रियल एस्टेट और खानपान, सुरक्षा, हाउसकीपिंग आदि जैसे कई सहायक उद्योगों को जन्म दिया है। आईटी सेवाओं और बीपीओ/आईटीईएस सेगमेंट में प्रत्यक्ष रोजगार का अनुमान 4.47 मिलियन है। वित्त वर्ष 2020–2021 में 1,38,000 लोगों (लगभग 36 प्रतिशत महिला कर्मचारियों से मिलकर) को जोड़ा गया है। अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन 12.0 मिलियन से अधिक होने का अनुमान है।

औद्योगिक उत्पादन – आईआईपी में 23.5 प्रतिशत की वृद्धिरू औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के माध्यम से परिलक्षित कारखाने के उत्पादन के पुनरुद्धार के संबंध में, अप्रैल–सितंबर

2021 के दौरान इसी अवधि की वृद्धि की तुलना में 23.5 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2020–21 के दौरान –20.8 प्रतिशत।

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना

भारत की विनिर्माण क्षमताओं और रोजगार सृजन को बढ़ाने के लिए, रुपये का परिव्यय। वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) 2021–22 से शुरू होने वाले विनिर्माण के 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये की घोषणा की गई है।

पीएलआई योजनाओं की घोषणा के साथ, अगले पांच वर्षों और उसके बाद उत्पादन, रोजगार और आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण सृजन की उम्मीद है। केंद्रीय बजट 2022– 23 के भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मानबीर भारत की दृष्टि को प्राप्त करने के लिए 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन को उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें 60 लाख नौकरियां पैदा करने की क्षमता है, और अगले के दौरान 30 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त उत्पादन हुआ है। पांच साल।

पीएलआई योजनाएं निम्नलिखित क्षेत्रों में शुरू की गई हैं:

1. प्रमुख प्रारंभिक सामग्री (केएसएम) / ड्रग इंटरमीडिएट्स (डीआई) और सक्रिय फार्मास्युटिकल
2. सामग्री (एपीआई)
3. बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण
4. चिकित्सा उपकरणों का निर्माण
5. इलेक्ट्रॉनिक / प्रौद्योगिकी उत्पाद
6. फार्मास्युटिकल दवाएं
7. दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद
8. खाद्य उत्पाद
9. सफेद सामान (एसी और एलईडी)
10. उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल
11. ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक
12. एडवांस केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी
13. कपड़ा उत्पादरू एमएमएफ खंड और तकनीकी वस्त्र
14. स्पेशलिटी स्टील
15. ड्रोन और ड्रोन घटक

स्टार्ट अप इकोसिस्टम: 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई स्टार्ट–अप इंडिया पहल में 19 एक्शन पॉइंट शामिल हैं जो पहल के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में कार्य करते हैं। पहल का उद्देश्य नवाचार और डिजाइन के माध्यम से स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाना है। इस पहल ने न केवल स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित किया है, इसने भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को

उत्प्रेरित किया है और घरेलू और वैश्विक जरूरतों के लिए अभिनव समाधान बनाने वाले भारतीय उद्यमियों को गति दी है।

पहल के शुभारंभ के बाद से, भारत को नौकरी चाहने वालों के बजाय नौकरी देने वालों के देश में बदलने के माननीय प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण में योगदान करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। 9 14 जनवरी 2022 तक, भारत 83 यूनिकॉर्न का घर है। +277.77 बिलियन का कुल मूल्यांकन। वर्ष 2019, 2020 और 2021 में प्रत्येक वर्ष क्रमशः 9, 10 और 44 यूनिकॉर्न के साथ कई भारतीय यूनिकॉर्न का जन्म हुआ। 11 ब्ट्प्क–19 ने सामाजिक–आर्थिक की एक बड़ी मात्रा का कारण बना है विश्व स्तर पर पीड़ित हैं, लेकिन यह इस समय के दौरान है जब लचीला भारतीय उद्यमियों ने न केवल अर्थव्यवस्था में योगदान करने के लिए बल्कि ब्ट्प्क–19 राहत प्रयासों में योगदान करने के लिए भी सहजता से काम किया।

मेक इन इंडिया: मेक इन इंडिया पहल 25 सितंबर, 2014 को निवेश की सुविधा, नवाचार को बढ़ावा देने, वर्ग निर्माण बुनियादी ढांचे में सर्वश्रेष्ठ निर्माण, व्यापार करना आसान बनाने और कौशल विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस पहल का उद्देश्य निवेश, आधुनिक और कुशल बुनियादी ढांचे के लिए अनुकूल माहौल बनाना, विदेशी निवेश के लिए नए क्षेत्रों को खोलना और सकारात्मक सोच के माध्यम से सरकार और उद्योग के बीच साझेदारी बनाना है। यह अनूठी श्वोकल फॉर लोकलश पहलों में से एक है जिसने भारत के विनिर्माण क्षेत्र को दुनिया में बढ़ावा दिया है। श्मेक इन इंडियाश पहल को विभिन्न उपायों के माध्यम से पूरे देश में लागू किया जा रहा है। इस क्षेत्र में न केवल आर्थिक विकास को उच्च पथ पर ले जाने की क्षमता है बल्कि हमारे युवा श्रम बल के एक बड़े पूल को रोजगार प्रदान करने की भी क्षमता है।

प्रमुख क्षेत्रों में भविष्य की नौकरी की भूमिकाएँ

स्किल इंडिया रिपोर्ट (2020) ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि उद्योग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स, एआर / वीआर और ऑटोमेशन जैसी नवीन तकनीकों को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिससे रोजगार के व्यापक अवसरों का विकास हो रहा है। मंडी। स्किल इंडिया रिपोर्ट (2018) बताती है कि भविष्य में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में स्थिरता और उपभोक्ता और पेशेवर सेवा उद्योगों में वृद्धि होगी। इसके अलावा, यह अनुमान है कि क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (प्वज) जैसी तकनीकों का उपयोग कंपनियों द्वारा तेजी से किया जाएगा और यह सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, शिक्षकों और वित्तीय एजेंटों जैसे व्यवसायों का समर्थन करेगा। इस तरह की तकनीक से सूक्ष्म उद्यमियों के लिए भी दरवाजे खुलने की उम्मीद है।

गिग अर्थव्यवस्था का उदय

रोजगार के रुझान में एक बड़ा बदलाव वैश्विक स्तर पर गिग अर्थव्यवस्था का उदय रहा है। गिग अर्थव्यवस्था में फ्रीलांसर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर, स्वरोजगार, ऑन–कॉल वर्कर और अन्य अस्थायी संविदा कर्मचारी शामिल हैं। गिग इकॉनमी का उदय तकनीक–सक्षम प्लेटफार्मों के उद्भव, लचीली कार्य व्यवस्था की मांग और कौशल पर ध्यान केंद्रित करने से प्रेरित है।

इंडिया स्टाफिंग फेडरेशन की रिपोर्ट (2019 के अनुसार, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और जापान के बाद विश्व स्तर पर फ्लेक्सी–स्टाफिंग में पांचवां सबसे बड़ा है। रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि फ्लेक्सी–स्टाफिंग उद्योग 22.7: की दर से बढ़ेगा, जो 2021 में 6.1 मिलियन कार्यबल तक पहुंच जाएगा। जबकि भारत में ब्लू–कॉलर नौकरियों (जैसे उबर, ओला ड्राइवर, अर्बनक्लैप) में गिग इकॉनमी प्रचलित है, वहीं गिग वर्कर्स की मांग सफेदपोश नौकरियां (जैसे परियोजना विशिष्ट सलाहकार, वेब और सामग्री डिजाइनर) भी उभर रही हैं। हालांकि गिग इकॉनमी कंपनियों के लिए लागत–कुशल व्यवस्था प्रदान करती है, भारतीय संदर्भ में एक प्रमुख चिंता इस श्रेणी के श्रमिकों (जैसे भविष्य निधि, बीमार अवकाश आदि) के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों की कमी रही है। सामाजिक सुरक्षा पर संहिता (2020) गिग अर्थव्यवस्था श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभों के कवरेज का विस्तार करके एक कदम आगे ले जाती है सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय पुश से लेकर रोजगार सृजन योजनाओं से लेकर कौशल विकास कार्यक्रमों में भारी वृद्धि के साथ किए गए उपायों की अधिकता को देखते हुए उभरते क्षेत्रों में नौकरी के बाजार में और गिग इकॉनमी का उदय और सामान्य रूप से महामारी के बाद अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार, आने वाले वर्षों में देश में रोजगार परिदृश्य आशाजनक दिख रहा है।

उपसंहार

रोजगार हमेशा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में माना गया है। भारत एक अत्यधिक आबादी वाला देश होने के कारण, रोजगार एक महत्वपूर्ण तत्व बन जाता है। स्किल इंडिया रिपोर्ट (2020) ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि उद्योग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स, एआर / वीआर और ऑटोमेशन जैसी नवीन तकनीकों को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिससे रोजगार के व्यापक अवसरों का विकास हो रहा है।

संदर्भ सूचि :

[1]. कपिला, उमा (2008–09), 1947 से भारत का आर्थिक विकास, अकादमिकनींव।

[2]. मिश्रा और पुरी, भारतीय अर्थव्यवस्था (2010) हिमालय पब्लिशिंग हाउस।

[3]. मिश्रा, एस.के. और वी.के. पुरी (2010) भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याएं, हिमालय पब्लिशिंग हाउस।

[4]. एनएसएसओ (2014), 2011–12 इकाई स्तर के आंकड़े, 68वें दौर, रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण, एनएसएसओ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। भारत सरकार। नई दिल्ली।

[5]. कोविड –19 के समय में नौकरी, काम और आय का नुकसान – पीएलएफएस डेटा का विश्लेषण, के पी कन्नन और मोहम्मद इमरान खान, ईपीडब्ल्यू, 8 जनवरी, 2022

[6]. एनएसएसओ (2014), 70वां दौर, जनवरी–दिसंबर, 2013 अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। भारत सरकार। नई दिल्ली।

[7]. ओईसीडी (2002), गैर–अवलोकित अर्थव्यवस्था को मापना

[8]. ढींगरा, ईश्वर सी. (2005); भारतीय अर्थव्यवस्थारू पर्यावरण और नीति; सुलतान चंद एंड संस; नई दिल्ली।

[9]. दीक्षित, ए.के. (996); द मेकिंग ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, द एमआईटी प्रेस।

[10]. ग्वार्टनी, जेम्स डी. और स्ट्रूप; रिचर्ड, एल। (1992); अर्थशास्त्ररू निजी और सार्वजनिक पसंद, छठा संस्करण।

[11]. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (2015), आधार वर्ष 2011–12 के साथ राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के संकलन के लिए असंगठित विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों पर उप समिति की रिपोर्ट.।